पाक्षिक

खबर आस पास

भारत सरकार से मान्यता प्राप्त समाचार पत्र

'जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की।'

संपादक :सत्येन्द्र राजवंशी मो. 9587570001 Email : khabaraaspass@gmail.com

वर्ष : 1 अंक : डिजिटल बीकानेर : गुरूवार 17 सितम्बर 2026 पृष्ठ : 4 मूल्य : 1.00 रुपया

अनंत नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार

मृदुल पत्रिका

नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने बुधवार को इसकी घोषणा की। उन्हें 22 सितंबर को गुजरात के केवडिया में आयोजित होने वाले 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनंत नाग को बधाई देते हुए कहा कि कई दशकों तक उनके सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा ने भारतीय सिनेमा, विशेष रूप से कन्नड़ सिनेमा पर मजबूत छाप छोड़ी है। अनंत नाग ने अपने लंबे फिल्मी करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। फिल्मों के साथ टेलीविजन पर भी उनकी पहचान बनी। आर.के. नारायण की कहानियों पर आधारित लोकप्रिय धारावाहिक 'मालगुडी डेज' में उनके अभिनय ने उन्हें देशभर के दर्शकों के बीच खास पहचान दिलाई। कन्नड़ सिनेमा के अलावा उन्होंने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया।

ओपीटी के लिए 40 हजार की जगह करीब 1 करोड़ रुपए शुल्क प्रस्तावित

अमेरिका में पढ़े विदेशी छात्रों के लिए नौकरी होगी महंगी!

3.63 लाख भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है असर, नियम अभी लागू नहीं

मृदुल पत्रिका

नई दिल्ली। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं नौकरी करने की योजना बना रहे विदेशी छात्रों के लिए बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। ट्रम्प प्रशासन विदेशी छात्रों के ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) कार्यक्रम पर करीब 1 लाख डॉलर यानी लगभग 96 लाख रुपए का शुल्क लगाने की तैयारी में है। अभी ओपीटी के लिए शुल्क इससे काफी कम है। प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले संबंधित लोगों और संस्थानों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसलिए इसे फिलहाल लागू नियम नहीं माना जा सकता। अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के लिए ओपीटी ऐसा कार्यक्रम है, जिसके तहत वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद संबंधित क्षेत्र में व्यावहारिक काम का अनुभव हासिल कर सकते हैं। सामान्य स्नातक छात्रों को आम तौर पर 12 महीने तक काम करने की अनुमति मिलती है, जबकि विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित यानी एसटीईएम विषयों के विद्यार्थियों को अतिरिक्त 24 महीने की अनुमति मिल सकती है।

AI जनरेटेड

भारतीय छात्रों पर बड़ा असर संभव

अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा ले रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक करीब 3.63 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या उन विद्यार्थियों की है जो पढ़ाई के बाद अमेरिका में काम करने के विकल्प पर विचार करते हैं। ओपीटी शुल्क में इतना बड़ा इजाफा होने पर छात्रों के सामने पढ़ाई के बाद नौकरी शुरू करने की लागत काफी बढ़ सकती है। यह खर्च पहले से मौजूद ट्यूशन फीस, रहने-खाने और अन्य शैक्षणिक खर्चों के अतिरिक्त होगा।

ओपीटी में भारतीयों की बड़ी हिस्सेदारी

अमेरिका में दो लाख से अधिक भारतीय छात्र ओपीटी के तहत काम कर रहे हैं। विदेशी विद्यार्थियों में भारतीयों की संख्या भी बड़ी है। ऐसे में प्रस्तावित शुल्क लागू होने पर भारत से अमेरिका जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए पढ़ाई के बाद रोजगार का रास्ता महंगा हो सकता है। अमेरिका में उच्च शिक्षा की फीस संस्थान और पाठ्यक्रम के अनुसार काफी अलग-अलग होती है। कई भारतीय परिवार पहले से ही शिक्षा शुल्क और रहने के खर्च के लिए बड़ी राशि खर्च करते हैं। ऐसे में ओपीटी शुल्क बढ़ने से कुल लागत में और इजाफा हो सकता है।

एसटीईएम छात्रों को मिलती है ज्यादा अवधि

ओपीटी की खासियत यह है कि इससे विदेशी छात्रों को अपनी पढ़ाई से संबंधित क्षेत्र में अमेरिका में काम करने का अवसर मिलता है। सामान्य पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए अवधि 12 महीने तक होती है, जबकि पात्र एसटीईएम पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को अतिरिक्त 24 महीने का विस्तार मिल सकता है। इस प्रस्ताव का असर खास तौर पर उन विद्यार्थियों पर पड़ सकता है, जो अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी के जरिए व्यावसायिक अनुभव हासिल करने और आगे रोजगार संबंधी विकल्प तलाशने की योजना बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 लाख डॉलर का ओपीटी शुल्क अभी लागू नहीं हुआ है। प्रस्ताव आगे की नियामकीय प्रक्रिया से गुजरना बाकी है।

ओबीसी आरक्षण पर सरकार बोली- आयोग के सर्वे के आधार पर तय हुआ कोटा

हाईकोर्ट में कहा- घर-घर सर्वे और उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के बाद सिफारिश; 41 जिला प्रमुख पदों में 5 ओबीसी के लिए आरक्षित, याचिकाकर्ता ने अनुपात पर उठाए सवाल

मृदुल पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार ने कहा कि स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों के आधार पर तय किया गया है। आयोग ने घर-घर सर्वे के साथ उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद आरक्षण की सिफारिश की थी। सरकार का जवाब ऐसे समय आया है, जब पंचायत चुनावों में प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी को लेकर प्रक्रिया चल रही है। जिला प्रमुख पदों के आरक्षण पर पहले ही सवाल उठ चुके हैं। 13 अगस्त को 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों की लॉटरी में ओबीसी के लिए पांच पद आरक्षित किए गए थे।

50 प्रतिशत की सीमा का सरकार ने दिया हवाला

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को मिलाकर आरक्षण निर्धारित करते समय 50 प्रतिशत की सीमा का पालन किया गया है। सरकार का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है।

दरअसल, जिला प्रमुख पदों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर राधेराम गोदारा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि पहले प्रदेश में जिला प्रमुख के 33 पद थे, जिनमें पांच ओबीसी के लिए आरक्षित थे। अब जिलों की संख्या बढ़ने के बाद जिला प्रमुख के पद 41 हो गए हैं, लेकिन ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की संख्या पांच ही रखी गई है। हाईकोर्ट ने इसी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा था। 13 अगस्त की लॉटरी में 41 जिला प्रमुख पदों में 8 एससी, 7 एसटी और 5 ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए। ओबीसी श्रेणी में ब्यावर और सीकर के जिला प्रमुख पद महिला ओबीसी के लिए आरक्षित हुए।

आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के जवाब पर आपत्ति जताई गई है। याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। उनका तर्क है कि जब 33 जिला प्रमुख पदों में पांच पद ओबीसी के लिए आरक्षित थे, तो 41 पद होने पर अनुपात के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या पर फिर से विचार होना चाहिए। याचिकाकर्ता पक्ष ने यह भी सवाल उठाया है कि पूर्व में ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत अलग रहा है, ऐसे में मौजूदा आंकड़ों और आयोग की सिफारिशों का आधार सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

बेसिक सैलरी 25 हजार तक तो पीएफ अनिवार्य, 12 साल बाद बदली सीमा

मृदुल पत्रिका

नई दिल्ली। बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर यदि आपकी मासिक राशि 25 हजार या इससे कम है, तो अब नियोक्ता के लिए पीएफ जमा करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कर्मचारी भविष्य निधि के लिए वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने का फैसला किया। सरकार के अनुसार इससे 51 लाख से अधिक कर्मचारियों को पीएफ बचत और पेंशन का लाभ मिलेगा। फिलहाल देश में करीब 7.89 करोड़ कर्मचारी पीएफ के दायरे में हैं। यह सीमा पूरी सीटीसी या सकल वेतन पर नहीं, बल्कि बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते पर लागू होगी। इससे पहले वर्ष 2014 में पीएफ के लिए वेतन सीमा 6,500 से बढ़ाकर 15 हजार की गई थी। यानी करीब 12 साल बाद इसमें बदलाव किया गया है।

ऐसे समझें नया नियम

बेसिक+डीए 20 हजार= कर्मचारी अनिवार्य रूप से पीएफ के दायरे में आएगा। 12 प्रतिशत के हिसाब से कर्मचारी के वेतन से 2,400 और नियोक्ता की ओर से 2,400 का योगदान होगा। कुल मासिक योगदान 4,800 होगा। बेसिक+डीए 30 हजार= 25 हजार की नई सीमा से अधिक वेतन होने पर नियोक्ता के लिए पीएफ कटौती अनिवार्य नहीं होगी। हालांकि कर्मचारी और कंपनी की सहमति से पीएफ जारी रखा जा सकता है। यदि 25 हजार की सीमा पर योगदान किया जाता है तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से 3,000-3,000 का योगदान होगा।

नई सीमा बढ़ने से पहले जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15 हजार से अधिक थी और वे अनिवार्य पीएफ दायरे से बाहर हो सकते थे, उनमें से बड़ी संख्या अब इसके दायरे में आ सकती है। इससे कर्मचारियों की दीर्घकालीन बचत बढ़ेगी और पात्र कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ भी मिलेंगे। पीएफ का योगदान कर्मचारी की तत्काल हाथ में आने वाली सैलरी को प्रभावित करता है।

AI जनरेटेड

तेज रफ्तार में करीब आया पीएनएस हुनैन

अरब सागर में भारतीय युद्धपोत से टकराया पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज

मृदुल पत्रिका

नई दिल्ली। उत्तरी अरब सागर में मंगलवार शाम भारत और पाकिस्तान के नौसैनिक जहाज आमने-सामने आ गए। पाकिस्तान का नौसैनिक जहाज भारतीय नौसेना के एक अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत के बेहद करीब पहुंच गया और दोनों में टक्कर हो गई। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार घटना अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई। हादसे में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। भारतीय युद्धपोत नियमित निगरानी अभियान पर था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी जहाज की पहचान पीएनएस हुनैन के रूप में हुई है। यह पाकिस्तान नौसेना का गश्ती पोत है। बताया गया है कि यह तेज रफ्तार से भारतीय युद्धपोत के करीब आया और उसके बाद असुरक्षित तथा गैर-पेशेवर तरीके से दिशा बदलने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों जहाजों के बीच टक्कर हो गई। भारतीय नौसेना के जहाज की पहचान अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है।

AI जनरेटेड मैप प्रतीकात्मक है।

दिल्ली में पाकिस्तानी राजनयिक तलब

घटना के बाद भारत ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को विदेश मंत्रालय में तलब किया। भारत ने पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के व्यवहार को अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी जहाज का आचरण अप्रैल 1991 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिक गतिविधियों की पूर्व सूचना से संबंधित समझौते के अनुच्छेद-10 के प्रावधानों के प्रतिकूल था। पाकिस्तान के अधिकारियों को सैन्य इकाइयों से समुद्र में अधिक सावधानी बरतने और दोनों देशों के बीच लागू समझौतों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस घटना से जुड़ा अहम तथ्य यह है कि टक्कर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई और फिलहाल किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है।

कवरेज के दौरान एनबीसी न्यूज का हेलिकॉप्टर क्रैश, 3 की मौत

लॉस एंजिल्स। अमेरिका के लॉस एंजिल्स में मंगलवार शाम समाचार कवरेज के दौरान एनबीसी न्यूज का हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलिकॉप्टर में सवार पत्रकार और पायलट समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हेलिकॉप्टर उस समय बस और एसयूवी की टक्कर से जुड़ी घटना की हवाई तस्वीरें और जानकारी जुटा रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही एनबीसी लॉस एंजिल्स ने अपनी लाइव कवरेज रोक दी। हेलिकॉप्टर में एरियल फोटो जर्नलिस्ट एलियाना मोरेनो और पायलट जॉर्ज मार्सिनिव सवार थे। दोनों की दुर्घटना में मौत हो गई। जमीन पर मौजूद एक व्यक्ति भी हादसे की चपेट में आया और उसकी जान चली गई। दमकल विभाग के अनुसार दो लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उनकी स्थिति के बारे में तत्काल जानकारी नहीं दी गई।

पीएम मोदी से मिले असगर अली, 8 दिन बाद जमीन विवाद में बड़ी राहत

मृदुल पत्रिका

भायंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के आठ दिन बाद उनके पुराने स्कूलमेट असगर अली वोहरा को महाराष्ट्र के भायंदर में लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद में बड़ी राहत मिली है। भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने विवादित भूखंड से कब्जा छोड़ने और निर्माण की अनुमति वापस करने की बात कही है। मेहता ने वोहरा के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने की बात भी कही है। 81 वर्षीय असगर अली वोहरा ने 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर जमीन विवाद में हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी रखी थी। वोहरा का कहना है कि उन्होंने गुजरात के वडनगर स्थित बीएन स्कूल में मोदी के साथ पढ़ाई की थी। मुलाकात के बाद महाराष्ट्र प्रशासन ने मामले में तेजी दिखाई।

वोहरा के अनुसार उन्होंने 1989 में भायंदर पूर्व के नवघर इलाके में करीब 2,810 वर्गमीटर जमीन खरीदी थी। उनका आरोप है कि 2011 में कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन को दो हिस्सों में बांटकर निर्माण कंपनियों के नाम कर दिया गया। इस मामले में 2015 में प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। वोहरा ने स्वयम बिल्डर्स और सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शंस पर जमीन से जुड़े विवाद में भूमिका होने का आरोप लगाया था। सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शंस को भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता से जुड़ी कंपनी बताया गया है। इन आरोपों पर संबंधित पक्षों का अपना पक्ष भी है और जमीन का विवाद लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में रहा है।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीरा-भायंदर नगर निगम ने मामले से जुड़े पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। इसके बाद महाराष्ट्र मंत्रालय में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी की मौजूदगी में बैठक हुई।

यूपीआई शुल्क पर सरकार बोली- विदेशी दबाव में नहीं लिया फैसला

राहुल गांधी ने अमेरिका को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया; 15 अक्टूबर से 2,000 से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर

सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती

मृदुल पत्रिका

नई दिल्ली। यूपीआई के चुनिंदा लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच विवाद बढ़ गया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि यूपीआई से जुड़े शुल्क का फैसला किसी विदेशी दबाव में नहीं लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जुड़े फैसले भारत की घरेलू जरूरतों और यूपीआई तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता को ध्यान में रखकर स्वतंत्र रूप से लिए गए हैं। सरकार के अनुसार 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 से अधिक के चुनिंदा व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) यूपीआई लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 प्रति लेन-देन रखी गई है। हालांकि यह शुल्क ग्राहक से नहीं, बल्कि संबंधित मर्चेंट भुगतान व्यवस्था में लिया जाएगा। 2,000 तक के भुगतान और व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) लेन-देन पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। सरकार के मुताबिक करीब 96 प्रतिशत मर्चेंट यूपीआई लेन-देन नए शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे।

राहुल गांधी ने फैसले पर उठाए सवाल

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर नए शुल्क की आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले से अमेरिकी कंपनियों को फायदा हो सकता है और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। कांग्रेस की ओर से भी फैसले को विदेशी दबाव से जोड़कर सवाल उठाए गए हैं। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यूपीआई से जुड़े निर्णय देश में स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

नए एमडीआर ढांचे को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। जनहित याचिका में नए नियम को रद्द करने की मांग की गई है। दूसरी ओर सरकार ने संकेत दिया है कि फिलहाल इस फैसले को वापस लेने या पुनर्विचार करने का सवाल नहीं है। सरकार का तर्क है कि यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ इसके बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और संचालन को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए नया ढांचा जरूरी है। जिरोधा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितिन कामथ ने भी नए एमडीआर ढांचे के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सामान्य व्यापारी और शेयर बाजार के ब्रोकर के बीच अंतर किया जाना चाहिए। कामथ के उदाहरण के मुताबिक, कोई ग्राहक 20 हजार का सामान खरीदता है तो व्यापारी को सीधे बिक्री से आय होती है।

बिहार में 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, यूपी में नदी ने बहाए 7 घर

पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड से आदि कैलाश मार्ग बंद; केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों को हेलमेट के साथ भेजा जा रहा, राजस्थान-मध्य प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट

मृदुल पत्रिका

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश अब भी परेशानी बढ़ा रही है। बिहार में 15 जिलों के करीब 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में बाढ़ और नदी कटान का असर है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के तेज कटान से सात मकान इसकी चपेट में आ चुके हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद हैं। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है।

बिहार में 575 पंचायतें बाढ़ की चपेट में

15 जिलों में बाढ़ से करीब 49.74 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के 88 प्रखंड, 575 ग्राम पंचायत, 2,642 गांव और 21 शहरी निकायों के 136 वार्ड भी प्रभावित बताए गए हैं। कई इलाकों में सामान्य जनजीवन बाधित है। कटिहार में स्कूल और कोचिंग केंद्रों में पानी भरने के बाद बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। कुछ जगह नावों से आवागमन और पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव अभियान जारी हैं। केंद्र की टीम भी नुकसान का आकलन करने बिहार पहुंची है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लखीमपुर खीरी के रूरा सुल्तानपुर गांव में शारदा नदी का कटान तेज हो गया है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार सात घर इसकी चपेट में आए हैं, जिनमें कुछ मकान और झोपड़ियां नदी में समा गईं।

पिथौरागढ़ में फिर बंद हुआ आदि कैलाश मार्ग

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दोबाट के पास भूस्खलन से आदि कैलाश मार्ग दोबारा बंद हो गया। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण सड़क और संपर्क मार्गों पर खतरा बना हुआ है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। चीरबासा के पास यात्रियों को सावधानी के तौर पर हेलमेट पहनाकर आगे भेजा जा रहा है। कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र में भूस्खलन के दौरान घोड़े-खच्चरों के मारे जाने की घटना सामने आई थी।

राजस्थान में 26 जिलों में येलो अलर्ट

राजस्थान में मानसून विदाई की ओर है, लेकिन बारिश का दौर अभी जारी है। मौसम विभाग ने 26 जिलों में 17 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। अजमेर, पाली समेत कई जिलों में मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई करीब 19 सितंबर से शुरू होने की संभावना है।

पूनरासर धाम में तीन दिवसीय ऋषि पंचमी हनुमानजी मेला महोत्सव 17 से शुरू, मेले की तैयारियां जोरों पर, प्रशासन ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

देराजसर (खबर आस पास)। श्री पूनरासर धाम में आगामी 17 सितंबर से शुरू होने वाले तीन दिवसीय ऋषि पंचमी मेला महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। मंगलवार को मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए श्रीडूंगरगढ़ एसडीएम झंवरलाल मित्तल, तहसीलदार श्रीवर्धन शर्मा, विकास अधिकारी मनोज कुमार, सेरूणा एसएचओ ईमीचंद, ट्रैफिक इंचार्ज कानाराम सहित बिजली, पानी एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी पूनरासर पहुंचे। अधिकारियों ने मंदिर परिसर सहित मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने श्रीपूनरासर हनुमानजी ट्रस्ट, पुजारी परिवार एवं गांव के मौजिज लोगों के साथ बैठक कर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, यातायात, पेयजल, बिजली, चिकित्सा, पार्किंग एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

श्री पूनरासर हनुमानजी ट्रस्ट की ओर से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर परकोटे सहित हनुमान भवन में बने करीब 200 कमरों का वितरण पिछले सोमवार से पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर शुरू कर दिया गया है। ट्रस्टी बजरंग लाल शर्मा ने बताया कि मेले के तीनों दिनों तक श्रीराम भोजनालय में बाबा का भंडारा चलेगा। श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने के लिए पूरे मंदिर परिसर में छाया के लिए टेंट लगाए गए हैं। पूनरासर पुजारी परिवार की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जयराम धर्मशाला में यात्रियों के लिए निःशुल्क कमरे, बिस्तर, भोजन एवं जल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़ की ओर से मोबाइल शौचालय एवं फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जा रही है। ट्रस्ट के सहयोग से कोठारी हॉस्पिटल की ओर से निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी, श्रद्धालुओं के लिए कतार व्यवस्था एवं विशेष दर्शन की व्यवस्था भी की जा रही है। बसों एवं छोटे चौपहिया वाहनों के लिए पूनरासर अंजनि माता मंदिर के पास निर्धारित स्थान पर पार्किंग स्टैंड बनाया गया है। वहीं दुपहिया वाहनों के लिए पीएचसी परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

पुलिस प्रशासन रहेगा मुस्तैद, फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरों से होगी निगरानी

मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश पर मेले में 500 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। पदयात्रा मार्ग पर सादावर्दी में पुलिसकर्मी निगरानी रखेंगे। मंदिर परिसर में फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। एएसपी, डीवाईएसपी सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी करेंगे। बिना नंबर के वाहनों, स्कार्फ बांधकर वाहन चलाने वालों, काले शीशे वाले वाहनों एवं तेज रफ्तार वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेले के तीनों दिनों तक मेला मार्ग पर थाना पुलिस एवं यातायात पुलिस लगातार गश्त करेगी। सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए इंटरसेप्टर बाइक एवं चौपहिया वाहन भी तैनात रहेंगे।

पूनरासर बाबा की आकर्षक गोल्डन फोटो फ्रेम का लोकार्पण

पूनरासर धाम में आयोजित ऋषि पंचमी हनुमान मेल को लेकर पुजारी परिवार भी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में मंगलवार को पूनरासर बाबा के आकर्षक गोल्डन फोटो फ्रेम का लोकार्पण किया गया। पुजारी विमल बोथरा, धनराज बोथरा, कमल बोथरा, संपतमल बोथरा, राजकुमार बोथरा रंजीत बोथरा, धर्मचंद बोथरा, लक्ष्मीपत बोथरा ने संयुक्त रूप से पूनरासर बाबा के दरबार में बाबा की गोल्डन फोटो फ्रेम का लोकार्पण किया। पुजारी विमल बोथरा ने बताया कि भादवा मेले में व्यवस्था बनाएं रखने के लिए असम, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली से पुजारी परिवार के 60 से अधिक सदस्य पहुंच चुके हैं।

सूडसर हनुमानजी का मेला 19 सितंबर को, तैयारियां शुरू

सूडसर गांव में स्थित प्रसिद्ध हनुमानजी मंदिर परिसर में 19 सितंबर को हनुमानजी का वार्षिक मेला आयोजित किया जाएगा। मेले को लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेले में सूडसर सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। हनुमानजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किशन स्वामी ने बताया कि मेले को लेकर मंदिर परिसर में आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेले में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न धार्मिक आयोजन एवं अन्य गतिविधियां भी होंगी।

जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पूनरासर मेले की तैयारियों का लिया जायजा

बीकानेर श्रेयांस बैद, (खबर आस पास)। जिला कलेक्टर निशान्त जैन और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बुधवार को पूनरासर गांव पहुंचकर यहां। भरने वाले मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अविलम्ब पूर्ण हो जाएं।

जिला कलेक्टर ने पदयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों पर पेचवर्क का कार्य अविलंब पूरा करने को कहा। साथ ही मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए बेरिकेडिंग की व्यवस्था भी करने के लिए निर्देशित किया।

जिला कलेक्टर ने कहा कि मेले के दौरान पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गांव में साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्था बेहतर रखने तथा मेला क्षेत्र में नियमित सफाई करवाने के लिए भी निर्देशित किया।

पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने मेले के दौरान सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन से संबंधित तैयारियों की जानकारी ली। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के मद्देनजर यातायात को सुचारु बनाए रखने, वाहनों की आवाजाही और पार्किंग सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने पूनरासर में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। विभिन्न धर्मशालाओं और अन्य स्थानों पर रुकने की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को मेला समाप्ति तक पूर्ण मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर रहने तथा आपसी समन्वय से व्यवस्थाएं संचालित करने के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि पूनरासर मेले के लिए श्रद्धालु बुधवार को पैदल और विभिन्न माध्यमों से रवाना होंगे। तीन दिवसीय मेला 17 से 19 सितम्बर तक आयोजित होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे।

कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए 15 अक्टूबर तक विशेष रबी गुण नियंत्रण अभियान

कृषि आदान निरीक्षक टीम ने कृषि आदान विक्रेता परिसरों का किया औचक निरीक्षण

बीकानेर श्रेयांस बैद, (खबर आस पास)। कृषि गुण नियंत्रण विशेष रबी अभियान के तहत कृषि विभाग के अधिकारी सहायक निदेशक उद्यान मुकेश गहलोत, उद्यानिकी अधिकारी अनिरुद्ध विश्नोई व लक्ष्मण सिंह शेखावत ने कृषि आदान विक्रेताओं परिसर का निरीक्षण किया व कृषि आदान व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।

उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से जिले में कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि आदान उचित मूल्य पर मिले यह प्रयास किया जा रहा है। किसानों को खाद के साथ किसी भी प्रकार टैगिंग ना किया जाए, इसके विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी गई। गहलोत ने बताया कि कृषि आदान बीज, उर्वरक व कीटनाशी प्रावधानों में उल्लेखित नियमानुसार ही कार्य करते हुए किसानों को कृषि आदानो की गुणवत्ता पूर्वक आपूर्ति सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जावेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विभाग नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि कृषि आदान विक्रेता जारी वैध लाइसेंस अनुसार ही कृषि आदानों की बिक्री वैधानिक तरीके से सुनिश्चित करें। विक्रय किए जाने वाले उत्पाद लाइसेंस पी.सी. में जुड़े होने चाहिए, साथ ही विक्रेता स्तर पर सेल पाइंट्स के अलावा गोदाम का भी इंद्राज होना अनिवार्य है।

निरीक्षण के दौरान अधिक क्रय/बार-बार खरीद करने वाले कृषकों से भी संवाद कर जैविक खेती/प्राकृतिक खेती, उर्वरको का विवेकपूर्ण उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया गया। प्रत्येक आदान विक्रेताओं के यहाँ पैकेज ऑफ प्रेक्टिस मे अंकित वैज्ञानिकों की सिफारिश अनुसार संतुलित उर्वरकों के उपयोग हेतु बैनर का प्रदर्शन करवाया जाना अनिवार्य है।उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने हेतु वैकल्पिक उर्वरक उपयोग/जैव उर्वरक के उपयोग को बढावा देने हेतु कृषकों/विक्रेताओं को प्रोत्साहित किया गया।

उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम प्रबंधन करते हुए मितव्यता के साथ उपयोग करने हेतु किसानों को प्रेरित किया गया।

बीकानेर के दो महाविद्यालयों में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2027 के तहत युवा संवाद एवं पंजीकरण कार्यशालाएं आयोजित

बीकानेर श्रेयांस बैद, (खबर आस पास)। विकसित भारत-2047 की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से चल रहे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग -2027 अभियान के तहत बुधवार को बेसिक पीजी कॉलेज तथा महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय में युवा संवाद एवं माय भारत पोर्टल पंजीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी देते हुए अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के जिला सह संयोजक गोपाल जोशी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा ही विकसित भारत-2047 की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में प्रयास ही पहचान बनाते हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हुए युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ नेतृत्व करने का आह्वान किया। जिला टीम के सदस्य हरिहर राजपुरोहित ने माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया, अभियान के विभिन्न चरणों तथा 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने भाई-बहनों, मित्रों और अन्य युवाओं को भी अभियान से जोड़ने का आग्रह किया।

जिला टीम के सदस्य अक्षय कुमार ने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित दीपक जोशी ने गुरुजनों के मार्गदर्शन, महापुरुषों के जीवन मूल्यों तथा राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

बेसिक पीजी कॉलेज के प्राचार्य सुरेश पुरोहित तथा महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य रजनी रमण झा ने विद्यार्थियों से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2027 में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।

कार्यक्रमों में दोनों महाविद्यालयों के प्राध्यापकगण, एनएसएस अधिकारी एवं जिला टीम के सदस्य उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितम्बर निर्धारित है और अभियान का उद्देश्य युवाओं की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना है।

बीकानेर की बेटी अनुष्का पारीक बनीं युवा जिला अधिकारी, रुद्रप्रयाग में संभाला पहला कार्यभार

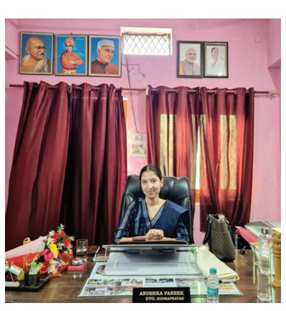

बीकानेर (खबर आस पास)। बीकानेर की प्रतिभाशाली बेटी अनुष्का पारीक ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर जिले का नाम रोशन करते हुए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में युवा जिला अधिकारी के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग पर कार्यभार संभाल लिया। इस उपलब्धि के साथ ही परिवार, रिश्तेदारों और बीकानेरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर जैसे ही कार्यभार संभालने की जानकारी सामने आई, बधाई संदेशों का सिलसिला शुरू हो गया। अनुष्का पारीक, घनश्याम पारीक एवं मीनाक्षी पारीक की पुत्री हैं। बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रही अनुष्का ने कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य तय करने के बाद उन्होंने दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा की तैयारी की और कठिन परिश्रम के बल पर प्रशासनिक सेवा में स्थान हासिल किया। रुद्रप्रयाग में पहली नियुक्ति पर कार्यभार संभालने का पल परिवार के लिए बेहद भावुक रहा। इस अवसर पर उनके पिता घनश्याम पारीक भी मौजूद रहे। बेटी को प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालते देख उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वर्षों की मेहनत और संघर्ष को सफलता में बदलते देख परिवार ने इसे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण बताया। परिजनों का कहना है कि अनुष्का ने बचपन से ही अपने लक्ष्य के प्रति गंभीरता बनाए रखी और अनुशासन व निरंतर मेहनत को सफलता का मंत्र बनाया। उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प और अथक प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अनुष्का पारीक की सफलता बीकानेर ही नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए भी प्रेरणा बनी है जो प्रशासनिक सेवाओं में जाकर देश और समाज की सेवा करने का सपना देखते हैं। उनकी नियुक्ति पर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, मित्रों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

पब्लिक पार्क में दौड़ी टॉय ट्रेन, लोटस पार्लर भी शुरू; बच्चों के चेहरों पर दिखी खुशी

बीडीए व मोदी डेयरी के एमओयू के तहत विकसित हुआ आकर्षण केंद्र, नेत्रहीन व स्कूली विद्यार्थियों ने ली पहली निःशुल्क सवारी

बीकानेर। शहर के पब्लिक पार्क स्थित लोटस टॉय ट्रेन पार्क में मंगलवार को टॉय ट्रेन और लोटस पार्लर का विधिवत शुभारंभ किया गया। अतिथियों ने फीता काटकर दोनों सुविधाओं का उद्घाटन किया। शुभारंभ के अवसर पर राजकीय नेत्रहीन छात्रावासित उच्च माध्यमिक विद्यालय के नेत्रहीन विद्यार्थियों तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सादुलगंज के विद्यार्थियों ने टॉय ट्रेन की निःशुल्क सवारी कर नई सुविधा का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं आगंतुकों के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई। उद्घाटन के बाद पार्क में पहुंचे बच्चों और अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने टॉय ट्रेन की सवारी का भरपूर आनंद लिया, जबकि अभिभावकों ने भी इस नई पहल की सराहना की। पार्क परिसर में दिनभर अच्छी-खासी भीड़ रही और नई सुविधा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही।

यह परियोजना बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) और मोदी डेयरी के बीच हुए एमओयू के तहत विकसित की गई है। माना जा रहा है कि टॉय ट्रेन पार्क आने वाले समय में शहर के प्रमुख मनोरंजन स्थलों में शामिल होगा। वहीं, लोटस पार्लर शुरू होने से पार्क में आने वाले लोगों को खान-पान की बेहतर सुविधा भी उपलब्ध होगी।

लोटस डेयरी के निदेशक अविनाश मोदी ने बताया कि टॉय ट्रेन बच्चों के मनोरंजन और सुविधा को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। ट्रेन में बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी सफर का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि निकट भविष्य में पार्क में खान-पान सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, जिससे आगंतुकों को बेहतर अनुभव मिल सके। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने कहा कि पब्लिक पार्क में मनोरंजन की नई सुविधाएं जुड़ने से शहरवासियों और पर्यटकों को एक नया आकर्षण मिलेगा। इस अवसर पर हनुमाना प्रसाद चम्पा देवी ग्रुप, मोदी डेयरी, लोटस डेयरी, मैसर्स अमर प्रताप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा एचपी मोदी स्कूल के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन अतिथियों और उपस्थित लोगों के आभार प्रदर्शन के साथ हुआ।

लूणकरणसर नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के चंद्रमोहन डाल और कांग्रेस के गणेशनाथ ने भरा नामांकन

लूणकरणसर (खबर आस पास)। नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने लूणकरणसर पंचायत समिति परिसर स्थित सभागार में नामांकन दाखिल किए। भाजपा के चंद्रमोहन डाल ने प्रधान कानाराम गोदारा और मंत्री के निजी सचिव बेगाराम ज्याणी के साथ नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस के गणेशनाथ ने नगर अध्यक्ष शाहनवाज और ब्लॉक अध्यक्ष अजय गोदारा के साथ नामांकन भरा। उपखंड अधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी दयानंद रूयल ने बताया कि नगर पालिका के 35 वार्डों में पार्षदों के चुनाव के बाद अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं।

गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस 3 अक्टूबर को बदले रूट पर चलेगी

बीकानेर (खबर आस पास)। पूर्व तटीय रेलवे द्वारा दानापुर मण्डल के राजेन्द्रपुल, हाथीदा अपर टॉल जंक्शन, रामपुर डुमरा एवं सोनपुर मण्डल के दिनकर ग्राम सिमरिया स्टेशनों पर तकनीकी कार्य किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की गाड़ी संख्या 15634 गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस 3 अक्टूबर को गुवाहाटी से रवाना होकर परिवर्तित मार्ग बरौनी-शाहपुर पटोरी-छपरा- वाराणसी-ज्ञानपुर रोड़-प्रयागराज होकर संचालित होगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह रेलसेवा मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, ईस्ट आउटर केबिन, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्टेशनों पर ठहराव नहीं करेगी।